चार विद्वान पत्रकारों के लेखों का संकलन

एकता यात्रा : अहम क़दम

भारतीय जनता पार्टी

(केन्द्रीय कार्यालय)

११, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001

प्रिय बंधुवर,

कन्याकुमारी से काश्मीर तक राष्ट्रीय एकता यात्रा ११ दिसम्बर १९९१ से अपने मार्ग पर बढ़ती जा रही है।

कुछ प्रमुख पत्रकारों ने अपने विभिन्न समाचार पत्रों में एकता यात्रा के बारे में अपने विचार प्रगट किए हैं।

यह पाँच लेखों का संग्रह है, जिसे निम्नलिखित पत्रकारों ने लिखा है। सर्वश्री

१. आर. के. करंजिया
२. एम. बी. कामथ (दो)
३. अरुण शौरी
४. के.आर. सुन्दरराजन

हमें इन लेखकों के सौजन्य से इस संग्रह को भेंट करते हुए प्रसन्नता है।

भवदीय,

(देवदास आप्टे)
कार्यालय सचिव

एकता यात्रा : अहम क़दम

● आर. के. करंजिया

इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं, जब सत्य राजनीतिक मतभेदों और सैद्धांतिक संघर्षों से परे और ऊपर हो जाता है। और, आज का यह अवसर तो निश्चित ही ऐसा है। भाजपा की विराट एकता यात्रा महान, पावन गंगा की तरह अपने मार्ग पर अग्रसर है और इस एकता यात्रा की वजह से भारत हिमालय की तरह स्वाभिमान से मस्तक उठाकर और साहस से सीना तानकर खड़ा हो गया है उन चुनौतियों के सामने, जो एक राष्ट्र के तौर पर उसके अस्तित्व को ही खतरे में डालने पर तुली हुई है।

हमारे धर्मनिरपेक्ष समाजवादी बुद्धिजीवी हमें इस विशाल प्रतीक के लिए क्षमा करेंगे। लेकिन असल में इससे कम और इसके अलावा और कोई प्रतीक नहीं हो सकता, जो उस ऊर्जस्वी चेतना और संगठन शक्ति के विराट कारनामे के समकक्ष हो, जिससे डा. मुरली मनोहर जोशी और उनके साथियों ने इस अभियान को मूर्त रूप दिया है।

कल्पना कीजिये पिछले सप्ताह के उस आश्चर्यचकित कर देनेवाले दृश्य की, जो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के संगम-स्थल कन्याकुमारी में स्थापित विवेकानन्द की विराट मूर्ति के इर्दगिर्द देखा गया। युग-युगांतर से खड़ी इस शिला पर समाधिस्थ होकर करीब ९९ वर्ष पहले विवेकानन्द ने स्वतंत्र, अखंड और प्रभुसत्तासंपन्न भारतवर्ष की परिकल्पना की थी; और आज फिर एक बार इतिहास अपने को दोहरा रहा था, लाखों

कंठों से पुकार उठ रही थी ''चलो, चलो कश्मीर चलो'', ''बचायेंगे, बचायेंगे कश्मीर बचायेंगे।'' और डा. जोशी, विवेकानन्द के सम्मुख संकल्प कर रहे थे कि उनके स्वप्न का संरक्षण करने के लिए वह अंतिम बलिदान देने के लिए उद्यत तथा प्रस्तुत हैं।

इस संकल्प और नारों के पीछे और 15,000 कि.मी. लम्बी 45 दिवसीय यात्रा के पीछे (यह यात्रा नहीं, यह तीर्थयात्रा है, एक पावन अभियान है – जोशी) राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक राष्ट्र-भक्तिपूर्ण प्रेरणा है, और वह है ''विघटनवाद और आतंकवाद से लड़ने के लिए राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय संकल्पशील को जागृत करना।''

निश्चय ही लक्ष्य है कश्मीर, जहाँ श्रीनगर के मशहूर लाल चौक में ये यात्री 1992 के गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं ताकि इस राज्य में भारत की ''खो चुकी'' प्रभुसत्ता को फिर से स्थापित किया जा सके।

सम्पूर्ण संगठन कार्य अपने लक्ष्य के अनुरूप ही श्लाघनीय है। वह अत्यंत राष्ट्रीय, धर्मनिरपेक्ष और प्रतीकात्मक है, फिर चाहे उसे हिंदुत्व कहा जाये या कुछ और। यात्रा अपने साथ न सिर्फ भारत के हरेक भाग से तीर्थजल और मिट्टी ले जा रही है, बल्कि वह भारत के भव्य इतिहास और सभ्यता-संस्कृति का भी एक साकार प्रतीक बनी हुई है।

गुरु तेगबहादुर और महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती के बलिदान के स्मारक आज के अकाली शहीद जीवनसिंह उमरांगल और शहीद भगतसिंह और राजगुरु और खेमकरण की लड़ाई में वीरगति पानेवाले अब्दुल हमीद जैसे नायकों की शहादत के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। अब्दुल हमीद के बेटे इस यात्रा में शरीक हैं। 100 मोटर वाहनों की इस यात्रा का नेतृत्व करने वाले दो रथों का संचालन सिख और मुस्लिम युवा कर रहे हैं। भगत सिंह के भाई ने एकता यात्रा की सराहना करते हुए कितना सटीक कहा है कि ''इससे स्वतंत्रता संग्राम की चेतना का पुनर्जागरण होगा।''

गति जीवन का नियम है, परिवर्तन का विधान है। खासकर भारतीय समाज के बँधे जल में यह अभियान ऐसे सामाजिक विस्फोट का माध्यम बन सकता है; यह अपने-आपमें उन लंबे-लंबे ऐतिहासिक कूचों की याद दिलाता है, जिनका श्रेय गाँधी, गैरी बाल्डी और माओ ज़ेडोंग को जाता है। और, शायद यही वजह है कि विघटनवादियों, आतंकवादियों और विघटन की अन्य शक्तियों के खिलाफ राष्ट्र को एकजुट करने के लिए किये गये इस अभियान की निंदा टुच्चे दिमाग और फूले अहंकारवाले बौने राजनीतिज्ञ कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरसिंहराव को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिये कि एकता यात्रा के खिलाफ उठे समवेत स्वरों के जाल में वह नहीं फँसे। उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया अलबत्ता धर्मनिरपेक्षता के भोंपुओं के भारी दबाव के बावजूद उनके परिपक्व विवेक को दर्शाती है। हालाँकि यह अभी पता नहीं चला है वह लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने को सहमत होंगे या नहीं, लेकिन सरकार के शीर्ष स्थान पर उनकी मौजूदगी से यह आश्वासन तो मिलता ही है कि यात्रा में अड़ंगा डालने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

भाजपा का मूलाधार व्यापक सांस्कृतिक और सभ्यतायुक्त हिंदुत्व है, मगर उसे परे रखते हुए उस पर ऊबा देने की हद तक लगनेवाला सांप्रदायिक उकसावे का आरोप, एक निरर्थक शत्रुता का स्वार्थपूर्ण षडयंत्र लगने लगा है, क्योंकि जाहिर है कि देश के विघटन के खिलाफ एक निर्भीक अभियान के आयोजकों को ''सांप्रदायिक'' शब्द के संकीर्ण और जातिवादी अर्थ में सांप्रदायिक नहीं कहा जा सकता। और, अगर वे ऐसे हों भी, तो यह विराट, राष्ट्रीय, देशभक्तिपूर्ण अभियान इच्छुक लोगों को सहज ही और अनिच्छुकों को जबरन, ऐसी नकारात्मक परिभाषाओं से ऊपर उठाके रहेगा।

और, फिर भाजपा के संदेह का फायदा देकर अपनी सच्चाई को प्रमाणित करने का एक मौका क्यों न दिया जाये, क्योंकि आखिरकार कोई

भी सच्चा भारतीय नागरिक इस तथ्य को नकार नहीं सकता कि आतंकवाद और विघटनवाद का निर्भयता से मुकाबला और खात्मा करना चाहिये। और न ही इस तथ्य को भी नकारा जा सकता है कि भाजपा ने उन लोगों के खिलाफ, जो भारत राष्ट्र को ध्वस्त करना चाहते हैं, एक विराट जन-आंदोलन गठित करने का एक अत्यधिक लोकतांत्रिक और कारगर रास्ता चुना है।

इतिहास पुकार रहा था – नहीं, झकझोर रहा था – सभी राजनीतिक पार्टियों को कि वे देशद्रोहियों के खिलाफ कोई साहसी और प्रतीकात्मक कदम उठायें लेकिन किसी ने परवाह नहीं की – या साहस नहीं किया कि कोई जवाब दे। भाजपा के आलोचक तो उन उग्रवाद-पीड़ित प्रदेशों में जाने तक की हिम्मत नहीं कर पाते। हो सकता है कि उनके पास वह मजबूत सदस्य आधारित शक्ति नहीं है, जो सिर्फ भाजपा के पास है। या शायद उनमें वह आत्मविश्वास और शक्ति नहीं है, जो मतदाताओं की मनपसंद पहली पार्टी, जो सिर्फ किस्मत के विचित्र कारनामे से दोयम पार्टी की भूमिका निभाने पर मजबूर हैं, बनने पर किसी पार्टी में आती है। उनके पिछड़ जाने की चाहे जो वजह हो, लेकिन वे भाजपा की इस बात के लिए आलोचना नहीं कर सकते कि उसने उस चुनौती को ऐसे विराट रूप में स्वीकार किया कि सारे राष्ट्र में चेतना की लहर दौड़ गयी।

लेकिन यात्रा के भाजपा-राजस्वं नेताओं एक बात से सतर्क रहना होगा। उन्हें अपने विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल और अन्य अग्रिम संगठनों में निहित गैरसामाजिक तत्वों से सावधान रहना होगा कि कहीं ये सांप्रदायिक या जातिवादी लहरें पैदा कर उनकी महान और स्वागतयोग्य यात्रा को मलिन और ध्वस्त न कर दें। एकता यात्रा तभी और सिर्फ तभी सफल हो सकेगी, जब देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जायेगी और दूसरे हर प्रकार के स्वार्थों या भुलावों से ऊपर उठा जायेगा।

* * *

क्या एकता अभियान की आवश्यकता नहीं है ?

● अरुण शौरी

राजनीतिज्ञों से लेकर स्तंभ लेखक तक चीख-चीख कर कह रहे हैं कि एकता यात्रा को रोका जाना चाहिए क्योंकि इससे अल्पसंख्यक नाराज हो सकते हैं।

सचमुच, यह चेतावनी मुसलमानों पर एक लांछन है क्योंकि यह उस धारणा पर आधारित हैं कि मुसलमान अन्य लोगों की अपेक्षा देश की एकता के प्रति प्रतिबद्ध हैं या वे नहीं चाहते कि आतंकवादियों को कुचल दिया जाय या वे यह नहीं चाहते कि श्रीनगर में तिरंगा फहराया जाय।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि अब तक कोई जिम्मेदार मुस्लिम नेता इस यात्रा से उत्तेजित नहीं हुआ है, जिससे उक्त धारणा की पुष्टि होती है। वे राजनीतिज्ञ जिन्होंने मुसलमानों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न करके अपना राजनीतिक जीवन चमकाया है वे स्तम्भ लेखक जिनका धर्मनिरपेक्षवाद दूसरे सम्प्रदायों को कोसने में बीता है, वही अपनी चीख-पुकार से समस्त मुस्लिम सम्प्रदाय पर लांछन लगा रहे हैं।

और इस प्रकार इन राजनीतिज्ञों आदि का काम लगातार जारी है। 'बांगला देश की ओर से भारत पर गुपचुप आक्रमण की तैयारी हो रही है।'

असम के विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है कि उसका मुकाबला किया जाएगा। उन्होंने अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए अति सूक्ष्म अध्ययन किया है। सभी लोग यह देख सकते हैं कि लाखों लोगों ने सीमा पार कर के असम की भूमि पर कब्ज़ा कर लिया है। जिस ढंग से फखरुद्दीन अली अहमद से लेकर अनवार तैमूर तक कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष राजनीतिज्ञों ने उनको चोरी-छिपे मतदाता सूचियों में दर्ज कराया है वह प्रमाणित है। और जब विद्यार्थियों ने शोर मचाया कि चुपचुप ढंग से देश के हस्तांतरण को रोका जाय तब उनके आन्दोलन को साम्प्रदायिक करार दे दिया गया। उन्हें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का अग्रिम पंक्ति का आदमी कहा गया। आजकल घुसपैठिये न केवल असम की भूमि पर कब्ज़ा कर रहे हैं वरन् बंगाल, बिहार और दिल्ली तक में ऐसा हो रहा है। देश के दूसरे छोर पर अकाली अपनी साम्प्रदायिक पार्टी के साथ मैदान में आ गये हैं। प्रत्येक धर्मनिरपेक्ष पार्टी उनसे मेलजोल रख रही है। स्तम्भ लेखक उनके मसलों और प्रस्तावों का समर्थन कर रहे हैं। उनको आगे लाने में श्रीमती गांधी एण्ड कम्पनी का योगदान रहा। जिन लोगों ने उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की या जिन लोगों ने उन्हें पूरे देश और विशेष रूप से सिखों के लिए अहित कर बताया उन्हीं को साम्प्रदायिक करार दे दिया गया। आज उसका नतीजा हमारे और विशेष रूप से सिखों के सामने है।

एक गरीब एवं वृद्ध बीमार महिला जिसे उसके पति ने निकाल दिया है उसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए और इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आदर किया जाना चाहिए, इसे साम्प्रदायिक करार दिया गया। एक किताब पर बिना पढ़े प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए उसे भी साम्प्रदायिक घोषित किया गया। वह पुस्तक जिसमें केवल हदीस (पैगम्बर के वचन एवं कार्य) हो उस पर किसी के साम्प्रदायिक कहने मात्र से प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, फिर भी उसे साम्प्रदायिक कहा गया। दूसरी ओर कहा जाता है कि एक मुस्लिम राजनीतिज्ञ ऐसा नक्शा प्रकाशित

कर रहा है जिसमें ऐसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र दिखाये गये हैं जिससे मुसलमान यह तय कर सकेंगे कि मुसलमान कहाँ-कहाँ हैं; यह भी कहा जाता है कि मुस्लिम संगठनों को विदेशों से मदद मिल रही है तथा यह धन खासतौर से इस्लाम के प्रसार और साम्प्रदायिक प्रचार तथा कार्य में प्रयुक्त हो रहा है। और यह भी कि दिल्ली और कश्मीर की मस्जिदें सभी राजनीतिक कार्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। राजनीतिज्ञ और स्तम्भ लेखक इन्हीं सब बेबुनियाद बातों पर अल्पसंख्यकों की भावनाओं के साथ खेलते हैं।

हमारी परिस्थितियाँ

इससे कौन इनकार कर सकता है कि आज हमें अपने देश को एक रखने के लिए एक जबरदस्त अभियान छेड़ने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि तोड़ने-फोड़ने का कार्य केवल पृथकतावादी तत्त्व ही कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने केन्द्र के विरुद्ध 'युद्ध' छेड़ देने की धमकी दी है, यदि उनकी असहिष्णु और असीमित मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। तमिलनाडु और कर्नाटक की स्थिति ऐसी हो गयी, जैसी कि चौ. रामास्वामी ने संकेत दिया है, कि कोई भी राजनीतिक पार्टी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच उत्पन्न कावेरी विवाद को सुलझा नहीं सकती। और पूरी की पूरी हिन्दू पट्टी में ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो जाति के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। कौन कह सकता है कि इन परिस्थितियों में हमें एकता के लिए एक जबरदस्त अभियान छेड़ने की आवश्यकता नहीं है।

और कौन कह सकता है कि इसके लिए कश्मीर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पंजाब नहीं बल्कि कश्मीर ऐसा स्थान है जो पिछले डेढ़ वर्ष से देश से बिल्कुल कट सा गया है। यही वह स्थान है जहाँ से सर्वाधिक संख्या में लोग गृह विहीन बना कर निकाल दिये गये हैं। पंजाब का अनुसरण करते हुए यही वह स्थान है जहां के संयमी राजनीतिज्ञ भी अब पृथकवादियों की

भाषा बोलने लगे हैं। अब उन्होंने भी यह घोषणा करना आरम्भ कर दिया है कि कश्मीर का भारत में शामिल होना 'विलय' नहीं बल्कि 'पदारोहण' था तथा कश्मीर को 1953 के पूर्व की स्थिति में आ जाना चाहिए। इन नेताओं ने न केवल इस मांग के लिये अपनी आवाज बुलन्द की है वरन् उसके हिसाब से कार्य भी शुरू कर दिया है। किन्तु इस प्रकरण पर देश में खतरे की घंटी जैसी बजनी चाहिए वैसा नहीं हुआ।

ऐसा अंशतः शायद इसलिए हो रहा है कि यह नेता कश्मीर में कुछ बात कहते हैं और दिल्ली में कुछ और। बड़े रूप में इसका यह कारण है कि देश का प्रत्येक भाग अपनी तात्कालिक समस्याओं में इतना उलझा हुआ है कि उसे यह देखने का मौका ही नहीं मिल पाता कि अन्य स्थानों पर क्या हो रहा है। पंजाब और कश्मीर की हत्याओं तथा नेताओं के विश्वासघात का दूरस्थ दक्षिणवासियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। क्या एक ऐसे जबरदस्त कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है जो कश्मीर की घटनाओं पर देश के प्रत्येक भाग को झकझोर दे, जागृत कर दे।

यह मामला केवल दक्षिण से लेकर कश्मीर तक को जागृत करने तक ही सीमित नहीं है। यह मामला उस राज्य के निवासियों को, जैसे जम्मू में शरणार्थियों को, आश्वस्त करने का है कि पूरा देश उनके कल्याण के प्रति सजग है। आज ये लोग कश्मीर मसले पर केवल उन्हीं लोगों की अर्थात उन्हीं राजनीतिज्ञों की आवाज सुनते हैं जिनके विषय में मैं कह चुका हूँ कि वे तीन-चौथाई भाषा पृथकतावादियों की बोलते हैं अथवा केन्द्र के उन गैर जिम्मेदार मंत्रियों की आवाज सुनते हैं जिनकी अज्ञानता और वाकपटुता जग जाहिर है। उदाहरण के लिए एस.बी. चह्वाण को ले लीजिए जिनके रुख से ऐसा जाहिर होता है कि देश को उन लोगों की जरा भी चिन्ता नहीं है। यदि वहाँ के देशभक्त लोगों की निष्ठायें पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है तो उनके लिये लाजमी है कि इन आवाजों के अलावा कुछ और आवाजें

भी सुनें जो देश के चारों तरफ से आ रही हैं। 'लेकिन डेढ़ महीने की अवधि तक चलने वाली यह यात्रा क्यों ? इतना लम्बा समय स्वयं में समस्यायें और तनाव उत्पन्न कर सकता है।'

यह वास्तव में शर्म की बात है कि देश के दो भागों में बंटने के केवल 45 वर्ष बाद लोगों को जागृत करने के लिए यात्रायें की जा रही हैं कि हम फिर से विभाजन की कगार पर पहुंच गये हैं। किन्तु हमारी स्थिति ऐसी ही है। आजकल हम जिन स्थितियों में रह रहे हैं उसमें यह आवश्यक है कि ऐसे प्रयासों को लम्बे समय तक चलाया जाय। हमारी राजनीति और हमारे राजनीतिज्ञों, हमारे दूरदर्शन और समाचार-पत्रों ने हमारी राष्ट्रीय जागृति को कुंठित कर दिया है। उनके प्रतिदिन के समझौतों और लड़ाई झगड़ों के समाचार, सीरियल और सिनेमा यह सब मिलकर हमें अन्य-मनस्क बना रहे हैं। देश कोई कार्य नहीं कर सकता। यदि इसकी जागरूकता को सामूहिकता का जामा नहीं पहनाया गया तो स्थितियों का सामना करते समय यह बीच में ही हथियार डाल देगा। अधिक लम्बे समय तक चलने वाला आन्दोलन, 'यात्रा' से कहीं अधिक समय तक चलने वाला अभियान ही विशाल जनसंख्या और विभिन्न प्रकार के लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है। एक ऐसी जागरूकता जो कई टुकड़ों में विभाजित हो चुकी है।

राजनीतिक लाभ

'किन्तु यह सब राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साधन हैं।'

इसमें कोई संदेह नहीं कि राजनीतिक लाभ उठाना भाजपा के उद्देश्यों में से एक है। किन्तु यह अच्छा नहीं है कि कोई राजनीतिक पार्टी हमारी एकता के मामले को उभार कर राजनीतिक लाभ अर्जित करें। हमें

आतंकवाद के खिलाफ मजबूत बनाने के बजाय हमारे बीच जाति एवं धर्म की दीवार खड़ी करे, जैसा कि कहा जाता है कि जनता दल कर रहा है या जैसा कि कांग्रेस ने समय-समय पर किया था।

हम ऐसे प्रयासों से अलग क्यों रहते हैं अथवा इन पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाते हैं ? हम देश की एकता और जागृति के लिये साथ-साथ क्यों नहीं चलते। बार-बार वही ढंग अपनाया जाता है। श्रीमती गांधी का सामना करने मेंन तमाम लोग किनाराकशी कर गये। उदाहरण के लिए, उन लोगों में, कम्युनिस्ट उनसे क्षमा प्रार्थी हो गये। जनसंघ ने जे.पी. के आह्वान का समर्थन किया। दूसरे उनसे अलग रहे तथा जे.पी. के आन्दोलन पर आर.एस.एस. द्वारा संचालित आन्दोलन होने का आरोप लगाया। पिछले दो वर्षों से किसी 'धर्मनिरपेक्ष' संस्था ने, किसी नागरिक स्वतंत्रता वाले संगठन ने, किसी धर्मनिरपेक्ष प्रधानमंत्री या भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने जम्मू में शरणार्थियों की सहायता उपलब्ध कराने के लिए उंगली नहीं उठाई जब कि वहां दो हजार से अधिक शरणार्थी हैं। एकमात्र ऐसे संगठन ही वहां राहत पहुंचा रहे हैं जो आर.एस.एस. से सम्बद्ध हैं किन्तु ऐसे प्रयासों को भी संकीर्ण माना जा रहा है।

'यात्रा' की स्थिति भी ठीक इसी प्रकार की है। भाजपा ने राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री से श्रीनगर में राष्ट्रीय झण्डा फहराने का निवेदन किया है। वास्तव में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद ही निस्संदेह ऐसा पद है जिस पर आसीन व्यक्ति देश के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय झण्डा फहरा सकता है। लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। मेरा आशय नरसिंह राव से नहीं है। पिछले वर्ष भाजपा की विद्यार्थी शाखा ए.बी.वी.पी. ने श्रीनगर में राष्ट्रीय झण्डा फहराने के लिए मार्च किया था। यद्यपि वे काफी बड़ी संख्या में थे किन्तु उन्हें रोक दिया गया। तब वे लौट कर दिल्ली आ गये और उन्होंने उस झण्डे को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह को सौंप दिया तथा उसे

श्रीनगर में फहराने के लिये निवेदन किया लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वह घटना भी याद होनी चाहिए जब मध्यपूर्व में हुई मौतों पर उन्होंने होली नहीं मनाई। इस बार भी अपनी यात्रा आरम्भ करने के पहले मुरली मनोहर जोशी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से श्रीनगर में झण्डा फहराने का आग्रह किया है। वे ऐसा करने को सहमत नहीं हैं। अन्य लोग इसे एक पार्टी का मसला समझ रहे हैं। यदि देश के सर्वोच्च अधिकारी प्रयास नहीं करते तो क्या नागरिक भी नहीं करें ?

और क्या श्रीनगर सही स्थान नहीं है ? क्या वह ऐसा स्थान नहीं है जहाँ झण्डा फहरा कर कोई अर्थपूर्ण घोषणा की जा सके ? क्या वह एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं जलाया गया ?

'किन्तु आप देखेंगे कि 'यात्रा' वहाँ के लोगों को इतना ज्ञान शून्य बना देगी कि जैसे-जैसे यात्रा कश्मीर के समीप आयेगी और अधिक संख्या में झण्डे जलाये जायेंगे।'

मान लीजिए कि वास्तव में ऐसा ही होगा। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होगा कि वहां आतंकवादियों की पकड़ इतनी मजबूत है अथवा पृथकतावादी भावनायें इतनी दूर-दूर तक फैली हैं उसे देखते हुए भाजपा ने जिस संघर्ष की शुरूआत की है वही समय की मांग है ?

हमें क्या करना चाहिये

पिछले कुछ वर्षों में शाहबानो, रुश्दी, मण्डल तथा अयोध्या जैसे विवादास्पद मसलों के अनेक दुर्भाग्यपूर्ण नतीजे सामने आये। किन्तु उनके कुछ सकारात्मक फल भी निकले। हमारे सम्भाषणों का दोहरा स्तर, हमारी राजनीति का घातक चरित्र तथा वोट बटोरने के लिए जाति और धर्म के दलालों की दरबारदार करने की ओर देश का ध्यान आकर्षित हुआ है। हमने अपने सभी धर्मों को परखना भी आरम्भ कर दिया है। इस्लाम

के विषय में विस्तार से ऐसा पहली बार हुआ है। यह भी एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यह इन परम्पराओं के विषाक्त तत्वों को दूर करने के लिए पहला कदम है।

भाजपा द्वारा आरम्भ की गई यात्रा इस प्रक्रिया को आगे बढ़ायेगी। जब तक इसे दूषित नहीं किया जायेगा, जब तक पेशेवर लोग इसे हत्याओं का माध्यम नहीं बनायेंगे, इसकी चुम्बकीय शक्ति हिन्दू और मुसलमानों में कोई विभेद उत्पन्न नहीं करेगी। बल्कि इससे देश तोड़ने वालों से देश जोड़ने वालों की संख्या अधिक हो जायेगी।

लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में अन्य लोग भाजपा को गलत कहने के बजाय उसका साथ देंगे कि वह देश की एकता को सुरक्षित रखने तथा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के राष्ट्रीय संकल्प और कश्मीर में भारत की सत्ता बरकरार रखने के लिए निकल पड़ी है।

और भाजपा को भी निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्या यात्रा को रोक देना चाहिए, क्या यात्रा के दौरान पार्टी द्वारा उठाये गये हिन्दुओं को उनकी सरकारों के भ्रष्ट आचरणों से डुबा देना चाहिए। इसे पार्टी नहीं बल्कि देश को नुकसान पहुंचेगा। जो काम उसने हाथ में लिया है वह पार्टी से कहीं अधिक बड़ा है।

* * *

एकता यात्रा अल्पसंख्यकों के विरुद्ध नहीं

● एम.वी. कामथ

एकता यात्रा के बारे में ऐसा क्या है जिससे कांग्रेस(इ) तथा वामपंथी दल इतने भयभीत हो रहे हैं। क्या इस कारण कि यह यात्रा सफल रहेगी ? या फिर कि उन दलों का अस्तित्व और घट जाएगा ? या इसलिए कि इससे युद्धरत लोगों का मिलाप हो जाएगा ? इसी प्रकार के संशय और भय तब प्रगट हुए थे जब लगभग पांच वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए एकात्मता यज्ञ का आयोजन किया था। उस समय गंगाजल के साथ भारत की सभी नदियों के जल का मिश्रण किया गया था और लोगों ने इसमें जिस उत्साह से भाग लिया था। हजारों लोग गंगाजल लेने के लिए पंक्ति में खड़े हो गए थे तथा ईसाइयों ने मूल रूप से हिन्दुओं के साथ मिलकर एकता का अद्भुत प्रदर्शन किया था। भारत की नदी गंगा, जो लोगों को कहीं प्रिय है, उसने लोगों को एक जुट बना दिया था। अलगाववाद की कटुध्वनि के बीच कांग्रेस को इसी प्रकार का एकात्मता यज्ञ करना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी को यह सम्मान सहज ही बटोर नहीं लेने देना चाहिए था। परन्तु स्पष्ट है कि कांग्रेस(इ) एक विकलांग पार्टी बनकर रह गई है। वह सकारात्मक कुछ कर ही नहीं सकती। यह केवल एक नकारात्मक व्यक्ति जैसी हो गई है जिसे किसी भी रचनात्मक बात पर 'नहीं' कहना है। कितने दुःख की बात

है।

अब इस पर विचार कीजिए :

देश फूट के नारों से तबाह हो रहा है। असम से शुरू करें। 'हिन्दू' (दिसम्बर 4) की खबर के अनुसार स्थिति यह है कि यद्यपि सरकार दावा कर रही है कि उल्फा की कमर टूट गई है और उसके नेता सब कुछ छोड़ अपने को बचाने के लिए भाग खड़े हुए हैं, परन्तु वास्तविक स्थिति एक अलग कहानी ही बयान करती है। 3 दिसम्बर को गुवाहाटी शहर के ठीक बीचों-बीच एक नौजवान व्यापारी की हत्या कर दी गई।

यद्यपि पंजाब में सेना तैनात कर दी गई है, किन्तु इससे आतंकवादियों द्वारा बार-बार हमले करने बंद नहीं हुए हैं। उन्होंने हरियाणा में हिसार जिले के टोहना कस्बे में 20 लोगों को गोली से उड़ा दिया। आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण लगभग डेढ़ लाख से ढाई लाख काश्मीरी लोग बेघरबार हो गए और सरकार के पास उन लोगों को कहने के लिए एक भी शब्द नहीं है। ये लोग अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं।

दक्षिण में, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य कावेरी जल पर झगड़ रहे हैं। कर्नाटक खुले आम उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवमानना कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष पी.वी. नरसिंहराव को कर्नाटक के मुख्यमंत्री को फटकार देना चाहिए था। इसकी बजाय वह तमिलनाडु और कर्नाटक को आपस में परामर्श कर अपने मतभेद दूर करने के लिए कह रहे हैं। अपने को बनाए रखने के लिए नरसिंह राव सीधे ही अपनी आँखें मूँदने का स्वांग रच रहे हैं।

इसके बाद एल.टी.टी.ई. का मामला अपने किस्म का एक ही मामला देखने को मिलता है। 'इण्डिया टुडे' (1 दिसम्बर) में कंपकपा देने वाली खबर में कहा गया है : राजीव गाँधी की हत्या करने के मामले के विशेष अन्वेषण दल और राज्य पुलिस (तमिलनाडु) 'क्यू' शाखा की जाँच से जो कुछ पता चलता है, वह यही है कि यह हत्या एक बड़ी योजना का छोटा

चलता है, वह यही है कि यह हत्या एक बड़ी योजना का छोटा सा भाग थी और उस बड़ी योजना में एक 'महा एलम' की योजना थी, जिसमें श्री लंका के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और तमिलनाडु को शामिल करना निहित था। एल.टी.टी.ई. ने अपनी घुसपैठ दूर तक कई राजनैतिक पार्टियों, राज्य सरकार और इसके पुलिस तथा गुप्तचर विभागों तक फैला ली है। क्या नरसिंह राव ने इस ओर ध्यान दिया है ?

ऐसी स्थिति में जबकि सभी राजनैतिक दलों के नेता मायावी अन्धभक्ति के रास्ते पर एक होकर चलने लगते हैं – जैसे कि कर्नाटक और तमिलनाडु की स्थिति में हुआ है, तो राष्ट्र को भारत पर आने वाले इस खतरे से सावधान करना जरूरी है कि भारत सोवियत संघ वाले रास्ते पर अग्रसर हो रहा है। ठीक यही काम भा.ज.पा. कर रही है। देश को बदनामी की हालत में डालने की बजाए उसे एकता का सन्देश देने का काम करने के लिए भा.ज.पा. को बधाई दी जानी चाहिए।

एक बात कही गई है कि एकता यात्रा तनाव पैदा कर सकती है। अप्रत्यक्ष रूप से इस में मुसलमानों की ओर संकेत किया गया है और इसका मतलब यह निकाला गया है कि इससे उनमें असंतोष हो सकता है तथा उपद्रव हो सकते हैं। मुसलमानों को या अन्य किसी भी सम्प्रदाय को एकता का विरोध करने की क्या आवश्यकता है ? मुसलमान यात्रा का विरोध कर सकते हैं, यह पूर्व कल्पना करना, राष्ट्र के एक भाग के प्रति आशंका व्यक्त करना है।

दूसरी बात में निहित है कि भा.ज.पा. के समर्थक मुरली मनोहर जोशी की एक नगर से दूसरे नगर तक यात्रा के दौरान उपद्रव भड़का सकते हैं। इस प्रकार का अर्थ लगाना न केवल द्वेषपूर्ण है बल्कि निन्दनीय भी है। ऐसा नहीं है कि यात्रा के दौरान सब कुछ ठीक ही रहेगा। अशांति हो सकती है। परन्तु क्या कोई शपथपूर्वक कह सकता है कि यह काम भड़काने वाले एजेण्टों का नहीं होगा ? देश में अनेक निहित स्वार्थ हैं जो चाहेंगे कि भा.ज.पा. को हर कीमत पर बदनाम किया जाए, यहाँ तक कि चाहे उससे

देश की शांति और स्थिरता को ही खतरा क्यों न हो ? यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भा.ज.पा. के अलावा अन्य पार्टियों को अपना उल्लू सीधा करना है।

यात्रा की सफलता भा.ज.पा. को श्रेय दिलाएगी और कांग्रेस(इ) को शर्मिन्दगी उठानी पड़ेगी; कम्युनिस्ट पार्टियों का भी यही हाल होगा, जिन्होंने भाषायी राज्यों और उनके बनाने के लिए संघर्ष किया तथा पहला राज्य जिसका प्रशासन उन्होंने संभाला वह था मुस्लिम प्रभुत्व वाला जिला, मालापुरम। कावेरी जल के बारे में कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच का विवाद देश के भाषायी विभाजन का ही विषपूर्ण परिणाम है।

एकात्मता यात्रा ने निःसन्देह यह सिद्ध कर दिया था कि लोग एकता चाहते हैं। हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, जैन और पारसी शांति तथा स्थिरता चाहते हैं। परोक्ष रूप में भी यह कहना कि वे इस यात्रा का विरोध कर सकते हैं, इन सम्प्रदायों का अपमान करना है। इससे भी अधिक, यह कहना कि एकता यात्रा आयोजित करने में भा.ज.पा. का कोई गुप्त उद्देश्य है, किसी भी अच्छे उद्देश्य का मजाक उड़ाना होगा। भाजपा को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में गम्भीरता पूर्वक समझना चाहिए और ऐसा क्यों न हो? क्या संविधान में इस पर कोई प्रतिबन्ध है।

और यात्रा, कश्मीर की घाटी में और ठीक श्रीनगर के बीच में आकर समाप्त क्यों न हो ? क्या कश्मीर भारत का अंग नहीं है ? क्या वह केवल इसलिए निषिद्ध क्षेत्र है, क्योंकि वहां अशांति है, और वह भी अशांति ऐसी जिसे पाकिस्तान ने फैला रखा है, जिसका वह समर्थन कर रहा है और जिसके लिए पूरा धन दे रहा है ? पिछले तीन चार वर्षों में आतंकवादियों ने तिरंगे को जलाया है और कोई स्वतंत्रता दिवस समारोह होने नहीं दिया है। क्या शेष राष्ट्र को खामोशी से राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रवाद का अपमान बर्दाश्त करते रहना चाहिए ? अगर भा.ज.पा. हिंदुत्व से राष्ट्रवाद की नीति अपना रही है तो हानि क्या है ? क्या किसी पार्टी को राष्ट्रवाद अपनाने का हक नहीं है जब केन्द्र में सत्ताधारी पार्टी इससे कोई विशेष

सरोकार नहीं रख रही।

कांग्रेस(इ) इस सिद्धांत पर चल रही है कि जो ना खुशगवार हो उसे भुला दिया जाए या छिपा दिया जाए। संडे मेल (1 दिसम्बर) ने खबर दी है कि दार्जिलिंग गोरखा हिल कौंसिल ने प्रभुतासम्पन्न 'गोरखालैण्ड' देश की स्थापना के बारे में पहला कदम यह उठाया है – जरा थोड़ी देर के लिए अपनी हंसी रोक लीजिए – कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने पिछले 11 वर्षों में इन पर्वतीय क्षेत्रों से जो अरबों रुपया इकट्ठा किया है, उसे वापस किया जाए।

आगे-पीछे इसी रूप में, महा नेपाल के प्रवर्तक नरबहादुर भण्डारी और उसकी सत्ताधारी सिक्किम संग्राम परिषद अगले चुनाव में भारत को सिक्किम से विलग करने के मुद्दे को इस आधार पर लेकर लड़ने का विचार कर रही है कि यह विलय 'जाली' था। यह हँस कर उड़ाने की बातें नहीं है। श्री घीसिंग भारत के लिए पहले ही काफी मुसीबत पैदा कर चुके हैं और वह फिर से युद्ध पथ पर चलकर आयकर, उपहार कर; केन्द्रीय उत्पाद कर, चाय बगान से हुई आय तथा इमारती लकड़ी की बिक्री की राशि वापस करने की मांग कर रहा है; उसकी यह भी मांग है कि गोरखालैण्ड आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई में मारे गए लगभग 1000 परिवारों में से प्रत्येक को 20 लाख रूपए का मुआवजा दिया जाए। श्री घीसिंग के पिछले रवैये को देखते हुए दार्जिलिंग जिले में और अधिक मुसीबत पैदा हो सकती है।

भा.ज.पा. क्या कर रही है – और इसके लिए वह धन्यवाद की हकदार है – वह भारत की अनिवार्य एकता को इस ढंग से केन्द्रित कर रही है, जो लोगों को अपील करती है और इस समय यह आवश्यक भी है। जब उल्फा पाकिस्तान से हथियार खरीदता है। जब घीसिंग सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और जब नरबहादुर भण्डारी चिल्लाकर कहता है कि वह भारतीय नहीं है तो क्या देश के लिए यह स्वीकार करने का समय नहीं आ गया है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है ?

भारत ने अपने मित्र देशों के साथ जो सहिष्णुता दिखाई है, वह हर

तरह की सीमा पार कर चुकी है। विभाजन के बाद हजारों बिहारी मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) छोड़कर चले गए, जो उसे अपना इस्लामी स्वर्ग समझते थे। और भी हजारों कराची तथा पश्चिमी पाकिस्तान के अन्य भागों में चले गए। हाल में ही उन्हें यह जान कर हैरत हुई कि हर जगह से वे दुतकारे गए। इससे वापसी का दौर शुरू हुआ, पहले असम में, जहाँ कांग्रेस(इ) अपना स्थायी वोट बैंक बनाने की गरज से चुपके से बसा दिया और फिर वे अन्य स्थानों में गए।

फिर क्या हुआ जब बंगला देश ने उन बिहारी मुसलमानों को बाहर धकेल दिया कि पाकिस्तान ने लगभग उन ढाई लाख लोगों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया, जिसके लिए पाकिस्तान विशेष रूप से बनाया गया था कि पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों के लिए स्वर्ग होगा। इसकी तुलना में 'हितवाद' में गिरिलाल जैन की रिपोर्ट है (और हमें मानकर चलना होगा कि लम्बे अर्से से चले आ रहे टाइम्स आफ इंडिया के यह सम्पादक जो कुछ कहते हैं, वह प्राधिकार से कहते हैं।) "बंगला देश से आए लगभग तीन लाख मुस्लिम विस्थापित अब भारत की राजधानी में ही हैं।" और न जाने कितने ही भारत के अन्य नगरों में होंगे। वही लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, वे ही अब भारत में सुरक्षा पूर्वक छिपे बैठे हैं।

जो भा.ज.पा. को दिन रात बदनाम करते हैं, वे जरा और सोचें। भारत की एकता और स्वतंत्रता बिकाऊ नहीं है। उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। एकता यात्रा इसी सुरक्षा के लिए है। यह अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई साधन नहीं है। एकता यात्रा को सर्वदलीय समर्थन मिलना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है कि सभी पार्टियाँ इसमें भाग लें और इसे राष्ट्रीय सफलता प्रदान करें। शेष सब कुछ गलत ही गलत होगा।

* * *
* *
*

भा.ज.पा. यात्रा राष्ट्र के क्षत घावों की मरहम

● आर. के. सुन्दरराजन

गृह मंत्री एस.बी. चव्हाण ने अपनी खास हकलाते से ढंग में एकता यात्रा के बारे में अपने विचार प्रगट किए : उन्होंने 'पायनीयर' के संवाददाता के सामने स्वीकार किया, "मैं असमंजस में हूँ कि क्या किया जाए, क्या न किया जाए।" यदि मैं उन्हें गिरफ्तार करता हूँ तो वे शहीद बन जाते हैं। वे गिरफ्तार होना चाहते हैं, परन्तु मैं ऐसा नहीं करना चाहता।" उन्होंने अफसोस प्रकट किया कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश नहीं दे सकते जो देश की अखण्डता में विश्वास रखता हो। श्री चव्हाण की उलझन का समाधान कैसे हो ? जब साक्षात्कार करने वाले दो रिपोर्टरों ने इसके समाधान के बारे में जोर देकर पूछा तो उन्होंने कहा, "या तो दंगे हो जाएं या इसी तरह की कोई घटना हो जाए।" उनकी पार्टी के उग्र धर्मनिरपेक्षवादी, जनता दल और वामपंथी दल भा.ज.पा. अध्यक्ष श्री मुरली मनोहर जोशी को गिरफ्तार करने के लिए शोर मचा रहे हैं। हालांकि श्री जोशी और श्री आडवाणी को निश्चय है कि दंगे या झगड़े नहीं होंगे, तथा यात्रा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करेगी, परन्तु उन्हें विश्वास है कि दंगे या झगड़े होकर ही रहेंगे।

दंगे होने के लिए दो तत्व उत्तरदायी हो सकते हैं। भा.ज.पा. के नेता

अपने कार्यकर्ताओं को तो रोक लेंगे, परन्तु विश्व हिन्दू परिषद के कुछ गर्ममिज़ाज कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं। दूसरी सम्भावना यह हो सकती है कि गैर भा.ज.पा. पार्टियाँ निरन्तर इन दंगों के निश्चित होने की बीन बजाती रहें और इससे ऐसा माहौल पैदा हो जाए, जिसके बारे में वे कहते हैं कि वे उसके लिए आशंकित रहे हैं।

भा.ज.पा. के एक वरिष्ठ सांसद ने मुझे संसद के केन्द्रीय हाल में बताया कि "ये नकली धर्मनिरपेक्षतावादी साम्प्रदायिक दंगों के लिए मचल रहे हैं।" आपस में छीछालेदर की बातें हमारी राजनीति का स्वाभाविक भाग बन गई हैं। संसद में और बाहर भी कांग्रेस, जनता दल और वामपंथियों ने जिस तरह से प्रचार फैलाया है, उससे अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा होने की सम्भावना को भी नकारा नहीं जा सकता। धर्मनिरपेक्षता के हामी "कार्रवाई" किए जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। वामपंथी विचारधारा की ओर झुकाव रखने वाले एक स्तम्भ लेखक ने कहा है कि सरकार श्री जोशी पर कुछ शर्तें लगा दे, इसके लिए अभी देर नहीं हुई है। मुसलमान विरोधी, सिखविरोधी या ईसाई विरोधी कोई नारे न लगाए जाएँ, "गद्दारों" के बारे में तीव्र भाषण न दिए जाएँ, न ही इस बात पर जोर दिया जाए कि केवल एक समुदाय ही राष्ट्रवादी है और गणतंत्र दिवस के समारोह के रूप में सामान्य रूप से ध्वजारोहण के अलावा श्रीनगर में अन्य कोई ध्वजारोहण न हो।

यही लेखक आगे लिखते हुए कहता है कि श्री जोशी को यह बता दिया जाए कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर या किसी भी एक साम्प्रदायिक उपद्रव की घटना होने पर इस यात्रा को किसी भा.ज.पा. शासित राज्य में पहुँचने से भी पहले प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ऐसे लोग भी जो भा.ज.पा. के बारे में बहुत अच्छा विचार नहीं रखते हैं, वह भी इस प्रकार के आदेश को ठीक नहीं समझेंगे। यदि कोई एक दंगे की घटना हो

जाती है तो बिना यह जाने कि यह दंगा किसने कराया और किसने उकसाया, कैसे यात्रा पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। बेशक भा.ज.पा. या विश्व हिन्दू परिषद की भीड़ कोई देवताओं का जमाव नहीं है। परन्तु यह भी कैसे माना जा सकता है कि यात्रा को बदनाम करने के लिए कांग्रेस, जनता दल या वामपंथी दल किराए पर लिए एजेंटों को भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे ? या मुस्लिम कट्टरपंथी भी इस तरह के उपद्रव करा सकते हैं। इसके अलावा, यह पूर्व कल्पना क्यों की जाए कि यात्रा में मुस्लिम विरोधी, सिख विरोधी या ईसाई विरोधी नारे लगाए जाएँगे ? ऐसा प्रतीत होता है कि स्वनाम धन्य धर्मनिरपेक्षवादी अत्यंत निराश होंगे, यदि भा.ज.पा. उनकी दुराशाओं के अनुकूल ठीक नहीं उतरती।

तर्क यह है कि वर्तमान यात्रा आडवाणी की रथ यात्रा से भिन्न नहीं है और श्री पी.वी. नरसिंहराव को पहले की तरह श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की वैसी अनिर्णय की स्थिति नहीं रहने देनी चाहिए, जब कि रथ यात्रा बिहार तक पहुंच गई थी। इस परामर्श में निहित अर्थ यही है कि श्री जोशी को तुरन्त गिरफ्तार कर लिया जाए। परन्तु यह बात सहज भुला दी गई है कि यदि श्री सिंह श्री आडवाणी को उसी दिन गिरफ्तार कर भी लेते जिस दिन वह रथ यात्रा शुरू हुई थी तो भी राजनैतिक प्रभाव कुछ अलग किस्म का नहीं होता।

यह श्री सिंह ही थे जिन्होंने मण्डल आयोग की विभाजनकारी रिपोर्ट की सहायता से वोट बैंक बनाने के आवेशपूर्ण निर्णय से अवसरवाद की राजनीति शुरू की। भा.ज.पा. की रथ यात्रा भी वैसी ही अवसरवादी प्रतिक्रिया थी। श्री सिंह ने भा.ज.पा. के वरिष्ठ नेताओं के साथ जो निजी तौर पर समझौता किया था यदि वे उसे निभाते तो इस यात्रा से उत्पन्न स्थिति को विफल कर सकते थे लेकिन श्री सिंह ने समझ का सन्तुलन खो

दिया । उन्हें निश्चित तौर पर अपने आप ही यह विश्वास हो गया था कि पिछड़े वर्गों, मुसलमानों तथा धर्म निरपेक्षवादी माने जाने वाले हिन्दुओं के ठोस वोट बैंक के आधार पर अपना ही संसद में बहुमत प्राप्त कर फिर प्रधान मंत्री बन जायेंगे । सौभाग्यवश श्री नरसिंहराव ने इस विवाद के बारे में अपना मस्तिष्क ठंडा रखा है और अपने समर्थकों के लगभग प्रभाव की स्थिति पर पहुंचने के बावजूद अपने को डावांडोल नहीं किया है । वह अपने गृह मंत्री की तरह उपद्रव होने की स्थिति का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं । उन्होंने श्री जोशी को जो पत्र लिखा है उससे पता चलता है कि उनकी चिंता वास्तविक है और इसमें कोई अन्य स्वार्थपूर्ण उद्देश्य नहीं है । उन्होंने लिखा:– अच्छा होता यदि आप कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने से पहले मुझसे और सभी राजनैतिक पार्टियों के नेताओं से परामर्श कर लेते । एकता यात्रा के आयोजन में सभी समुदायों के सहभागी होने का सर्वदलीय कार्यक्रम कहीं बेहतर होता । यदि हम संयुक्त राजनैतिक इच्छा का प्रदर्शन कर सकें तभी हम राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी ताकतों को एक दृढ़ और प्रभावकारी संकेत देने में सफल हो सकते हैं ।

मेरे विचार में श्री रामकृष्ण हेगड़े ने इस मामले में समुचित ध्यान केन्द्रित किया है जब उन्होंने बम्बई के एक संवाददाता को बताया कि ''यदि यह यात्रा राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए है तो आपत्तिजनक नहीं है परन्तु ऐसी यात्राओं का वास्तविक प्रयोजन राजनैतिक लाभ उठाना होता है । रथ यात्रा के बारे में आज भी हमें पुरानी बातें याद आती हैं जो अच्छी नहीं लगती । किन्तु यदि श्री जोशी की यात्रा पूरी तरह से और वास्तविक रूप से विभिन्न समुदायों के बीच सद्भावना और भाई-चारे को बढ़ाने की है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है ।''

जैसा कि श्री हेगड़े ने कहा है कोई भी राजनैतिक दल बिना किसी राजनैतिक उद्देश्यों को सामने रखे हुए किसी यात्रा का आयोजन नहीं

करेगी । जब राजीव गाँधी कांग्रेस अध्यक्ष थे तो उन्होंने कांग्रेस(इ) की जो सद्भावना यात्रा की थी उसका उद्देश्य निश्चय ही कोई परोपकार की भावना से नहीं जुड़ा था । इसका उद्देश्य – और यह उद्देश्य बिल्कुल वैध उद्देश्य था कि मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों का समर्थन चुनाव में फिर से प्राप्त किया जाय । इसलिए इस समय जबकि काश्मीर और पंजाब जल रहे हैं, ऐसे समय में यदि भा.ज.पा. राष्ट्रीय एकता के लिए अपने आपको इस यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का सबसे मजबूत पहरेदार बताकर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहे तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता । राजनीति कोई मानवप्रेम का आदर्श नहीं है इसमें सत्ता में आने की खोज रहती है । भा.ज.पा. ने बड़ी बुद्धिमता पूर्वक यह महसूस किया कि अधिक से अधिक लोग भारत के भविष्य को एक अखण्ड इकाई के रूप में देखने के लिए चिंतित हैं । देश की विखण्डता का खतरा बहुत दूर दिखाई नहीं पड़ता है । सम्भव है कि कालावधि में यह आशंकायें निर्मूल सिद्ध हो परन्तु जिस तरह से पिछले पांच वर्षों में केन्द्र में आने वाली विभिन्न सरकारों ने काश्मीर, पंजाब और असम की समस्याओं पर कार्रवाई की है, उससे यह प्रभाव व्यापक रूप से फैला है कि देश का नेतृत्व पूरी तरह से अक्षम हाथों में है । जब कुछ स्थानों में राष्ट्रगीत गाया नहीं जा सकता या भारतीय धरती पर राष्ट्रध्वज नहीं फहराया जा सकता, इससे राष्ट्रीय सम्मान को चोट पहुंची है और मन में गहरी अपमान की भावना पैदा हुई है।

मैं नहीं समझता कि यदि एकता यात्रा को बिना रोक टोक के अपने गंतव्य तक जाने दिया जाता है तो भी निर्दोष लोगों का रक्त बहाए बिना श्रीनगर में राष्ट्रीय तिरंगा फहराया जा सकता है । भा.ज.पा. के कार्यक्रम का यह भाग खतरनाक रूप से अयथार्थवादी है । काश्मीर घाटी में भारत के प्रति अन्यदेशीय भावना इतनी अधिक है कि जब तक वहाँ एक लाख अतिरिक्त सैनिक तैनात न कर दिए जाएं और वहां कि सारी जनता को

बंद दरवाजों में न रखा जाए तब तक वहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया नहीं जा सकता । यह निश्चित ही काश्मीर में 'भावनात्मक अखण्डता' लाने का ढंग नहीं है ।

यात्रा को भली प्रकार से गुजरने देना चाहिए और इसे अमृतसर में समाप्त कर देना चाहिए । वास्तविक तीर्थयात्रा के भाव में श्री जोशी और भा.ज.पा. के अन्य नेताओं को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जाना चाहिए और कुछ गिने चुने सिक्खों द्वारा किए जा रहे भयावह गलत कृत्यों के लिए उन्हें क्षमा कर देने की याचना करनी चाहिए । कितना अच्छा हो यदि प्रधान मंत्री भी व्यक्तिगत रूप से इस सद्‌भावना से जुड़ जाएं जो घावों पर मरहम लगाने जैसा काम करेगा ।

* * *
* *
*

एकता को खतरा और हमारा धर्म

● एम.वी. कामथ

यूरोप में दो प्रकार की एक दूसरे से विपरीत घटनाएं हो रही हैं, जिसे भारत को सबक सीखने की आवश्यकता है । यू.एस.एस.आर. के नाम से विख्यात सोवियत संघ टूटता जा रहा है, यदि हम मान भी लें कि वह अभी टूटा नहीं है । इसके अनेक घटक राज्यों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया है । इनमें से तीन अत्यधिक महत्वपूर्ण रूस के स्लाविक गणराज्य, उक्रेन और बायलोरशिया ने एक राष्ट्रकुल बना लिया है, जिसका प्रधान कार्यालय बायलोरशिया की राजधानी मिंस्क में होगा और अन्य राष्ट्रों से इसमें शामिल होने को कहा गया है ।

तीन गणराज्यों के नेताओं द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि "अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा भौगोलिक राजनैतिक वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में अब यू.एस.एस.आर. का अस्तित्व समाप्त हो गया है । सम्भवतः इसके स्थान पर स्वतंत्र राज्यों के एक राष्ट्रकुल की स्थापना होगी । जो इस राष्ट्रकुल में शामिल नहीं होना चाहेंगे, वे अपनी इच्छानुसार जिस रूप में कार्य करना चाहेंगे, उसके लिए स्वतंत्र होंगे ।

जिस तेजी से सोवियत संघ खण्ड-खण्ड होता जा रहा है, वस्तुतः वह आश्चर्यजनक है । कुछ पता नहीं, आगे क्या होगा । यह ठीक है कि जिन तीन गणराज्यों ने सोवियत 'राष्ट्रकुल' में रहने को चुना है, वे

यू.एस.एस.आर. के सबसे बड़े गणराज्य हैं। इन्हीं की धरती पर सबसे अधिक परमाणु हथियारों के भण्डार हैं। अब इन भण्डारों का क्या होगा, उनकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायित्व किस पर होगा ? क्या इन तीन गणराज्यों के नेता अर्थात रूस के जनप्रिय नेता बोरिस येल्टसिन, उक्रेन के राष्ट्रपति लियोनिड क्रावचुक तथा बायलोरशिया के सर्वोच्च नेता स्तानिसला शुशकेविच स्वयं अपने प्रयोग के लिए संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग इन पर अनाधिकृत कब्जा कर लेंगे। क्या सोवियत संघ और अमेरीका के बीच हुई पुरानी संधियाँ अब वैध रहेंगी या इन पर पुनः बातचीत होगी ? कोई भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। फिर करेंसी (मुद्रा) का प्रश्न भी है। क्या पृथक हुए राज्यों में वर्तमान मुद्रा मान्य रहेगी ? क्या उनका अवमूल्यन होगा ? भूतपूर्व यू.एस.एस.आर. के घटक राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय आर्थिक सम्बन्धों तथा अन्य देशों के बीच व्यापार जैसे रूस और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? यहाँ भी कोई कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकता।

पुरानी व्यापारिक संधियों को लागू करने के बारे में भारत किससे अपील करेगा ? भूतपूर्व रूस के साथ भारत के बड़े पैमाने पर व्यापार को देखते हुए इन प्रश्नों का महत्व और सार्थकता और भी बढ़ जाती है।

यह तो एक प्रकार की घटनाएं हैं। अब मास्ट्रिश्ट जो कुछ हुआ, उस पर विचार करें, वहाँ यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्यों ने भारी बहुमत से 1999 तक एक सिंगल करेंसी और समान केन्द्रीय बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया। इसे ऐतिहासिक निर्णय कहना, इस वर्ष की इस घटना के बारे में कम कह कर बताने वाली ही बात होगी। यह घटना मात्र आर्थिक घटना नहीं है। यह उससे कुछ अधिक ही है। यह एक ऐसी राजनैतिक घटना है जो 1948 में सरदार पटेल द्वारा भारत के राज्यों को एकीकृत करने की घटना के बाद ऐसी घटना सुनने में आई है। और

चीन में सभी युद्ध नेताओं को समाप्त कर एक समन्वित राज्य प्रशस्त हो गया है।

चीन में एकता का सूत्रपात काफी रक्तपात के बाद हुआ था। भारत में सरदार ने अपना जादू डाल कर 500 से अधिक छोटे बड़े राज्यों को एक ही छत्रछाया में स्थित कर दिया था। यूरोप में, विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप में रक्तहीन क्रान्ति पहले ही हो चुकी है। यूरोप एक समन्वित राज्य के रूप में उभर कर आ रहा है। इसी संदर्भ में पूर्ण रूप से नई यूरोपीय मुद्रा के समझौते की सार्थकता है, जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 12 देशों में से 11 देशों में मान्य होगी।

बारहवें देश ब्रिटेन को अभी इस बारे में निर्णय करना है कि वह इस मुद्रा संघ में शामिल हो या नहीं। परन्तु इससे अन्य 11 देशों में इस योजना के कार्यान्वयन पर प्रभाव नहीं पड़ा है। डच प्रधानमंत्री रूड ल्यूबर्स ने कहा है: ''अगर हमने एक सदस्य राज्य की बात सुनी होती तो हमने मुद्रा-संघ और सामाजिक यूरोप की अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन की गति को धीमा कर दिया होता। हमने ऐसा नहीं किया और हम उस सदस्य देश को छोड़कर अपनी योजना पर आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि पहले भी हुआ है कि बाद में वह सदस्य शामिल हो सकता है।'' निस्सन्देह, इसमें ब्रिटेन का संदर्भ है, जिसने उस समय यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय साझा बाजार के विचार को विफल बनाने का प्रयास किया, जब पहली बार इन पर विचार किया गया। ब्रिटेन ने इनमें शामिल होने से इंकार किया और बाद में लगभग उसने शामिल होने की याचना की। इसलिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्यों की बात समझ में आ सकती है कि यदि वे यह विश्वास करें कि पहले की तरह ब्रिटेन मुद्रा-संघ का सदस्य बनने की फिर मांग करेगा और पौंड स्टर्लिंग गुजरी हुई बात बनकर रह जाएगा। सिंगल करेंसी शीघ्र ही वास्तविक रूप में सामने आएगी। वर्ष 1999 की सीमा तो

आखिरी सीमा है, आश्चर्य नहीं कि यह मुद्रा-संघ उससे बहुत पहले व्यावहारिक रूप ले ले।

मुद्रा-संघ का समझौता आखिरकार इतने ऐतिहासिक महत्व का क्यों है? स्वतंत्र करेंसी राष्ट्रीय सम्प्रभुता की निशानी है। देश चाहे जितना छोटा हो, वह अपनी करेंसी रखना चाहता है। राष्ट्रीय करेंसी का त्याग करने का अर्थ यह है कि वह देश अपनी सम्प्रभुता के एक भाग को छोड़ने को तैयार है। पश्चिम यूरोप निश्चित ही एक संयुक्त राज्य यूरोप की ओर अग्रसर हो रहा है। इस तरह एक तरफ सोवियत संघ है जो बिखर रहा है, दूसरी तरफ विश्व के कुछ अत्यंत विकसित देश हैं, जो निकट आ रहे हैं, स्वेच्छा से अपनी सम्प्रभुता का एक भाग छोड़ रहे हैं। सोवियत संघ को कभी 'सुपर-पावर' समझा जाता था। अब वह ''सुपर'' तो नहीं ही है। हमें तो यह भी आश्चर्य है कि क्या वह कोई ''पावर'' भी रह जाएगा। क्या रूस को एक ''पावर'' के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाएगी ? या फिर उक्रेन ''पावर'' के रूप में सामने आयेगा ? संयुक्त राष्ट्र संघ में ''वीटो'' का प्रयोग कौन कर सकेगा, जिसका अधिकार आज सोवियत संघ को है ? इसके अलावा, यदि संयुक्त राज्य यूरोप पूरी तरह अस्तित्व में आ जाता है, जिसकी सम्भावना दिखाई पड़ती है, तो क्या नए संघ के दो घटक राज्य, ब्रिटेन और फ्रांस को अलग-अलग वीटो का अधिकार रहेगा ? ऐसा कैसे हो सकता है ? और यदि यह अनुमत्य न हो तो ''वीटो'' की शक्ति का क्या होगा जो सुरक्षा परिषद में अत्यंत शक्तिशाली साधन है।

इन सब स्थितियों को देखते हुए भारत को किस दिशा में जाना चाहिए, यह स्पष्ट है। इसको और अधिक समन्वित होना चाहिए। न केवल इसलिए कि एकता में ही शक्ति होती है, बल्कि इसलिए भी कि इसकी विपरीत स्थिति ''विखण्डता में विनाश है'' और भी अधिक सार्थकता रखती है। असम की अत्यंत दुःखपूर्ण स्थिति, जिसमें पृथकता की मांग की

रखती है। असम की अत्यंत दुःखपूर्ण स्थिति, जिसमें पृथकता की मांग की जा रही है और उतनी ही डी.एम.के. की गिरोहबंदी, जिसमें वह एल.टी.टी.ई. को अंधाधुंध समर्थन दे रही है, के परिप्रेक्ष्य में याद रखना चाहिए कि कमजोर भारत का अर्थ है कमजोर असम, कमजोर पंजाब और कमजोर तमिलनाडु।

इसी प्रसंग में एकता पर बल देने वाली भा.ज.पा. की रथ-यात्रा विशेष अर्थ और सार्थकता ग्रहण कर लेती है। देश की इस मूलभूत एकता के बिना कुछ भी सम्भव नहीं है। इस एकता के होने पर सब कुछ सम्भव है। किसी को भी और कहीं भी भारत की अनिवार्य एकता पर घात नहीं करने देना चाहिए।

हम एक कदम और आगे बढ़कर कह सकते हैं कि भारत की एकता से भी अधिक महत्वपूर्ण दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप की एकता की सम्भावना है, जिसे हम बहुत कुछ भूल गए हैं।

परन्तु यदि भारत विखण्डित हो गया तो दक्षिण एशिया की एकता दूर की बात ही रह जाएगी। देश के प्रति निष्ठा की भावना धीरे धीरे कम होती जा रही है और पहला काम इसे रोकने का होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षवाद की लगातार दुहाई देते हुए कट्टरपंथियों के सामने झुकने से सत्ताधारी पार्टी के ढोंग में वृद्धि ही होती है। भारतीय जनता पार्टी को ''केसरिया ब्रिगेड'' और उसके उद्देश्य को 'केसरिया उद्देश्य'' का नाम देकर इसे नकारने से कांग्रेस(इ) तथा वामपंथी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सम्मानजनक नहीं बन जाती हैं। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही थी, जिसने केरल में मुस्लिम बहुल जिले की स्थापना की और यदि देश में कोई ऐसी पार्टी है जिसका धर्मनिरपेक्षता के मामले में कोई स्थान नहीं है तो वह यही देशद्रोही पार्टी है जिसने मूलतः ''भारत छोड़ो'' आन्दोलन के दौरान न केवल कांग्रेस को धोखा दिया, बल्कि साम्प्रदायिक आधार पर देश के विभाजन को समर्थन दिया। केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है; केसरिया वस्त्र धारण कर के ही राजपूत अलाउद्दीन खिलजी और दूसरों से लड़ने गए

थे और युद्ध क्षेत्र में उन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे। जो भा.ज.पा. का मखौल उड़ाना चाहते हैं, बेहतर हो अधिक सावधान रहें। टेलीग्राफ भा.ज.पा. की निंदा करने में अग्रणी रहा है, उसने भी वास्तविकता को पहचान लिया है। हाल में एक सम्पादकीय (8 दिसम्बर) में उसने लिखा है: ''धर्म निरपेक्षता के कहे जाने वाले प्रवर्तक भा.ज.पा. छाप की राजनीति को इतना अधिक नापसंद करते हैं कि वे प्रायः ठीक जड़ों में तेजी से हो रहे ध्रुवीकरण को भी भूल जाते हैं।'' ठीक यही बात है। जितना अधिक भा.ज.पा. को अपमानित किया जाएगा, लोगों से उतना ही समर्थन प्राप्त होगा। निःसन्देह भा.ज.पा. 'विखण्डता' के भय के आधार पर पोषित हो रही है, परन्तु वह क्यों न हो? काश, कांग्रेस(इ) और वामपंथी दल जो कुछ हो रहा है, उसके प्रति अधिक सजग होते। दुःख की बात है कि जो सच है, जिसके बारे में 'टेलीग्राफ' ने ठीक ही लिखा है: ''कठोर यथार्थताओं का सामना करते हुए ''राजनैतिक वर्ग'' भीरू बन रहे हैं।'' अपने खास अन्दाज में फारूख अब्दुल्ला भले ही श्रीनगर में अतिरिक्त अर्थात तिरंगे के अलावा अन्य कोई ध्वज फहराने के विरुद्ध तर्क देते रहें, परंतु अधिकांश नागरिकों को यह विश्वास नहीं होता है कि काश्मीर में अलगाववाद का वस्तुतः कोई खतरा नहीं है।

इस गम्भीर खतरे को देखते हुए एकता की मांग हिन्दु कट्टरता में कहाँ आती है? यह तो देश की वह सेवा है जो कोई देशभक्त ही कर सकता है। पाकिस्तान के भारत को काटकर छोटे करने के प्रयास का यह सही और लगभग सम्पूर्ण उत्तर है। जो भी एकता का विरोध करता है, वह पाकिस्तान के हाथों में खेल रहा है'।

सबसे अच्छी बात जो कांग्रेस कर सकती है, वह यही है कि वह एकता यात्रा में अर्थपूर्ण रूप से शामिल हो जाए, ताकि इस्लामाबाद तक यह संदेश पहुँच जाए कि जहाँ तक एकता का सवाल है, वहाँ सभी पार्टियाँ एक हैं।

* * *

वज्र संकल्प

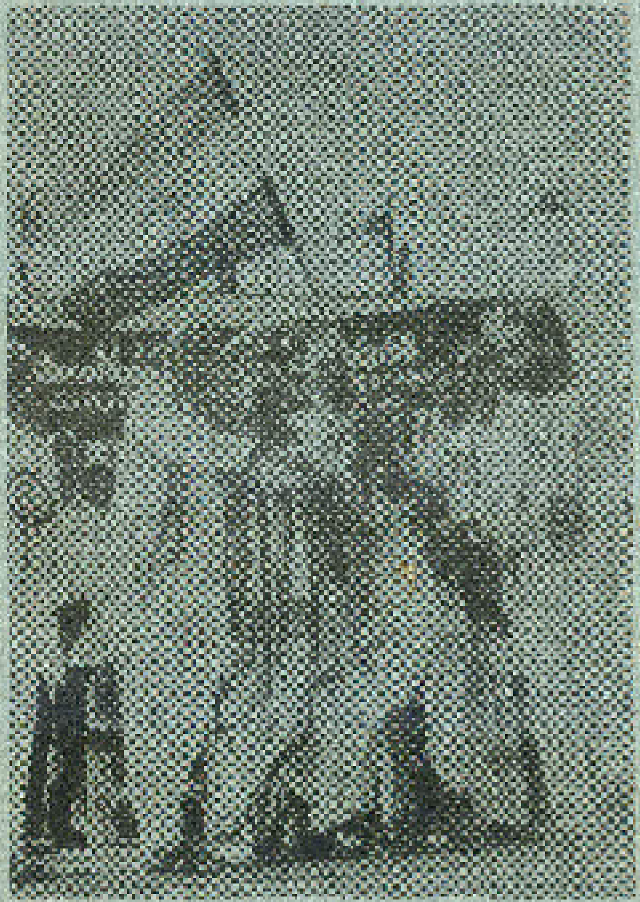

श्री देवदास आप्टे, कार्यालय सचिव, केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी,
११ अशोक रोड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं राघव प्रिंटर्स,
करोल बाग नई दिल्ली द्वारा मुद्रित